बेनिफिट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गयी सिंचाई परियोजनाओं की भारी संख्या पूरी नहीं हो पायी है ;

(ख) कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं बनायी गयी हैं और उनमें से कितनी परियोजनाओं को 1991 के अंत तक पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) अपूर्ण परियोजनाओं पर दिसम्बर, 1991 के अंत तक कितनी राशि व्यय की गयी है और उन्हें पूरा करने के लिये कितनी और राशि की आवश्यकता होगी तथा कितना समय लगने की आशा है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं का प्रतिपादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा प्रतिपादित की गयी परियोजनाओं की संख्या के बारे में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है न ही राज्यों द्वारा प्रतिपादित की गयी सभी परियोजनाएं उनके द्वारा ही क्रियान्वित की जाती है । सातवीं योजना के अंत तक किए गए आकलन के अनुसार, वर्ष 1951 से 1990 की अवधि के दौरान 255 वृहद् और 1070 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी थीं । इनमें से, वर्ष 1990 के अंत तक 83 वृहद और 777 मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं ।

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक अपूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 20,020 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी है तथा इनको पूरा करने के लिए 36,210 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है । सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में लिया गया समय निधियों के आबंटन, राज्यों द्वारा प्रदान की गयी पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है ।

**भूमि पर कृषि**

2693 **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 186 मिलियन हैक्टेयर कृषि-योग्य भूमि पर कृषि की जाती है, यदि हां, तो कितनी भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा चुका है और इसे सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कब से लाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सिंचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो यह लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कौन-कौन सी नई तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कर लेने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (कृषि वर्ष 1987–88 के लिए नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, 184.943 मिलियन हेक्टेयर कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से सकल सिंचित क्षेत्र 56.216 मिलियन हक्टेयर है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

**मध्य प्रदेश में कैलों नदी-बांध का निर्माण**

2694. **श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री कृपा करेंगे कि : यह बता की

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कैलों नदी-बांध का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना स्वीकृति हेतुभेजी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितने समय से लम्बित पड़ी है और इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कैलों सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु मई, 1988 में केन्द्र में प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार ने बांध अभिकल्प, निर्माण सामग्री तथा भूजल के संबंध में मुद्दों को हल करना है । इसे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरण तथा वन दृष्टि से स्वीकृति, कोयले वाले क्षेत्र की जलमग्नता के वास्ते कोयला विभाग से सहमति तथा उड़ीसा सरकार से उनके सीमा क्षेत्र की भूमि जलमग्न होने के वास्ते सहमति भी प्राप्त करनी है ।

**Utilisation of water from rivers**

2695. DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whethter Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the 'Statesman' of February 6, 1992, under the caption '52 per cent surface water being utilised', and if so, what is the total quantity of water available to the country in a year from rivers and rainfall, and the quantity that is utilised;

(b) what is the quantity of water which ' remains unutilised and goes waste; and

(c) whether Government have prepared plans to utilise the water that is so far not utilised, and if so, what is the quantity of water out of the unutilised water at present which is likely to be utilised by the end of 1990s?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA); (a) and (b) Yes, Sir. Out of 4000 cubic kilometres of average annual precipitation (snow and rainfall) received by the country, the utilisable water resources is assessed at 1140 cubic kilometres of which about 552 cubic kilometres is being presently, utilised leaving 558 cubic kilometres of utilisable water as unutilised.

(c) 168 major and 288 medium irrigation projects envisaging increased utilisation of surface water arc currently under implementation spilling over from the 7th Plan. The quantity of unutilised water which is likely ' to be utilised by the end of 1990s has not yet been assessed in the absence of finalisation of Eighth and subsequent plans.

**Modernisation of Godavari Delta System**

2696. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have cleared the "Modernisation of Godavari Delta System" in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c) The modified project report on • modernisation of Godavari Delta System in Andhra Pradesh estimated to cost Rs. 226 crores was received in the Central Water Commission in February, 1991 for techno-economic appraisal. It envisages remodelling of canals, lining of canals in selected reaches, providing gates to sluices, construction of masonry sluices in place of existing pipe sluices, providing communication links etc. The Screening Committee of Central Water Com- mission examined the report and opined that goal of modemisatjoa and its justification are not clearly reflected in the report. Therefore, the